दै. स्वदेश, भोपाल
21 OCT 2010

उद्योग नीति के बहाने

स्थानीय जनों को खास अवसर देना महत्वपूर्ण

अपने बेहद शांत और समरस प्रकृति के बावजूद उद्योग की दृष्टि से मध्यप्रदेश कभी उद्योगपतियों के आर्कषण का विषय नहीं बन पाया। जबकि तमाम सरकारों ने इस दिशा में कोशिशें कीं। लगता है कि मप्र को एक नए तरीके से देखने के लिए लोग तैयार नहीं है। एक शांत और अपेक्षाकृत सहज राजनीतिक शैली मप्र की एक खूबी है। बावजूद इसके राज्य का औद्योगिक विकास कुछ इलाकों तक सीमित है। पूरा मप्र आज भी बड़े उद्योंगों के इंतजार में है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आदिवासी संस्कृति के एक आर्कषण और शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता के नाते मप्र की पहचान तो है किंतु उसे नए समय के साथ चलना आज भी सीखना है। इस दिशा में मध्यप्रदेश सरकार की नई उद्योगनीति के मसौदे पहली नजर में तो आकर्षित करने वाले हैं। राज्य के स्थानीय निवासियों को 50 प्रतिशत रोजगार की अनिवार्यता भी इस नीति को खास बनाती है। मप्र के मूल निवासियों के प्रति राज्य सरकार की यह दृष्टि स्वागत योग्य है। साथ ही एक हजार से से ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योग अगर स्थानीय निवासियों को 90 प्रतिशत तक स्थानीय लोगों को रोजगार देंगें तो उन्हें दो साल तक टैक्स, आदि में छूट का फायदा होगा। उम्मीद की जानी चाहिए इस उद्योग नीति के बहाने राज्य सरकार ने जो पिटारा खोला है वह राज्य के लिए लाभकारी साबित होगा। मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक अच्छी सोच के साथ उद्योग नीति को अपनी स्वीकृति दी है। उद्योग समूह इससे राज्य में निवेश के लिए आकर्षित हो सकते हैं और मप्र कुछ समय सही मार्ग पर चलकर एक उदाहरण बन सकता है। उद्योग लगाने के नाम पर लाभ उठाकर डिफाल्टरों पर भी इस नीति में कुछ पाबंदियां हैं। जाहिर तौर पर मप्र के पास विकास के सभी अवसर हैं। बस नीतियों, कार्यक्रमों और सही दृष्टि से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। राज्य सरकार के प्रयास बताते हैं कि वह इस दिशा में गंभीर है। पिछले समय को देखने के बजाए, आगे देखने और आगे बढ़ने का समय है। राज्य में कायम राजनीतिक स्थिरता ने सरकार को एक अवसर दिया है कि वह इस समय का उपयोग करते हुए आगे बढ़े और कुछ करके दिखाए। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री और उनके युवा व उत्साही मंत्रिमंडल के पास मप्र को वास्तव मे स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने का अवसर मौजूद है। सत्ता के माध्यम से मप्र के सपनों में रंग भरने का यही समय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने भाषणों में इन्हीं भावनाओं के इर्द-गिर्द लगातार अपनी बात भी कहते हैं। किंतु समाज के योगदान के बिना सपने सच नहीं होते। सामाजिक सहभागिता और सहकार से बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। मप्र की सरकार को सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में नहीं समाज जीवन के हर क्षेत्र में एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ना है। सरकार और नौकरशाही की सीमाओं और काम करने के तरीकों के बावजूद परिवर्तन हमें ही लाना है। एक आदर्श कार्यसंस्कृति का विकास करते हुए राज्य आगे बढ़े इसके लिए सबको जतन करना होगा। शायद तभी हम मप्र को एक प्रगतिशील राज्य बना पाएंगें।